सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-30 अंक-9 7 मई, 2015 पृष्ठों की संख्या 8 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

जनआन्दोलन गठित करने की शपथ के साथ देश भर में मनाया गया एसयूसीआई (सी) का 67वां स्थापना दिवस – 24 अप्रैल

24 अप्रैल को भारत के मेहनतकश वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर आर्फ इण्डिया(कम्युनिस्ट) के 67वें स्थापना दिवस देश के विभिन्न प्रान्तों में जनजीवन की ज्वलंत मांगों को लेकर जनआन्दोलन गठित करने की शपथ लेते हुए मनाया गया।जनसभा की शुरूआत पार्टी के संस्थापक क्रान्तिकारी नेता व महान मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गान से हुई समापन अन्तर्राष्ट्रीय गीत से हुआ।

भोपाल, मध्यप्रदेश : 24 अप्रैल को बेतहाशा बढ़ती मंहगाई, खाद, बिजली को मंहगा करने, भूमि अधिग्रहण से किसानों की जबरन जमीन हड़पने, पानी, ईलाज, शिक्षा की अराजकता, स्कूल व रेल सेवाओं के निजीकरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और अपराधों के बीच एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) के 67वां स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय जनसभा का आयोजन स्थानीय नीलम पार्क में जोश-खरोश के साथ हुआ। इस सभा मे मध्यप्रदेश के भोपाल के अलावा गुना, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, इन्दौर, रायसेन, विदिशा, अलिराजपुर, देवास, आदि जिलों से पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, समर्थक व हमदर्द शामिल हुए। सभा शुरू होने से पहले विभिन्न जिलों से आए

भोपाल में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

साथियों ने क्रान्तिकारी व प्रगतिशील गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में पार्टी व तमाम जन संगठनों द्वारा चलाए गए आंदोलनों व महान मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

सभा को पार्टी के अन्यतम वरिष्ठ नेता, पोलित ब्यूरो सदस्य एवं केन्द्रीय ट्रेड यूनियन ए.आई.यू.टी.यू.सी. के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती ने संबोधित किया। अपने संबोधन में अन्य बातों के साथ उन्होंने कहा कि मोदी व शिवराज सरकार जनविरोधी नीतियां व नाजायज फैसले थोपकर धन्नासेठों के लिए मुनाफे का पहाड़ खड़ा कर रही है और मजदूर-किसानों, मेहनतकशों का खून चूसने वाली शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था को पोषित कर रही है। देश में नौकरियां छीनी जा रही हैं। हर जगह काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है और असल वेतन घट

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भूकम्प-पीड़ित नेपाल के लोगों की मदद करें

एसयूसीआई(सी) की अपील

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 27 अप्रैल को जारी एक बयान में कहा : 25 अप्रैल (शनिवार) को आए विनाशकारी भूकम्प ने पड़ौसी देश नेपाल सहित भारत के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में भारी तबाही मचाई है। नेपाल घाटी के अलावा भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। अब तक नेपाल में 3000 लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं और अभी भी हजारों लोगों के मलबे के तले दबे होने की आशंका है। हजारों लोगों का सभी से सम्पर्क टूट चुका है। वे जगह-जगह फंसे हुए हैं। उन्हे बचाना है। ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदा से नेपाल के लोगों का सामना पहले कभी नहीं हुआ।

उत्तरी और पूर्वी भारत में भी भूकम्प का असर पड़ा है। खास कर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान 60 लोगों के मरने की खबर सुनी है।

संकट की इस घड़ी में भूकम्प-पीड़ितों की मदद में हाथ बंटाना सभी विवेकशील लोगों का फर्ज बनता है। देश के सभी रहमदिल नागरिकों से एसयूसीआई(सी) की केन्द्रीय कमेटी अपील करती है कि राहत कोष में दिल खोल कर चंदा दें। आपदा प्रभावित लोगों को मदद पहुँचाने के लिए दवाइयों और नगद या चैक के जरिये धन का सहयोग करें।

पता : 48 लेनिन सरणी, कोलकाता 100013
फोन नं. : 22683234.

हमें एकता चाहिए, वोटों के लिए नहीं, जुझारू वर्ग संघर्ष व जनआन्दोलन गठित करने के लिए

सीपीआई(एम) पार्टी कांग्रेस में कॉ. प्रभाष घोष

विशाखापटनम : *आन्ध्रप्रदेश के विशाखापटनम में 14 से 18 अप्रैल तक सीपीआई(एम) पार्टी की 21वीं कांग्रेस हुई। उद्घाटन समारोह में बुलाये जाने पर एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने जो वक्तव्य दिया वह इस प्रकार है:*

कॉमरेड सभापति, कॉमरेड प्रकाश करात, सीपीआई (एम) के महासचिव प्रकाश करात और सीपीआई(एम) के पोलित ब्यूरो के सदस्यगण, अन्य वामपंथी पार्टियों के नेतागण और कॉमरेड डेलिगेट्स,

मैं अपनी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ और आपकी पार्टी कांग्रेस के इस उद्घाटन सत्र में हमारी पार्टी को आमंत्रित करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

कॉमरेड्स, आपकी पार्टी कांग्रेस हमारे देश के अभूतपूर्व संकट की घड़ी में आयोजित की जा रही है। देश में आपकी सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी होने के नाते आपके फैसलों और बाद में उनके क्रियान्वयन पर भारत के वामपंथी आन्दोलन का भविष्य काफी हद तक निर्भर करता है। बहुत अर्सा पहले लेनिन ने बताया था कि एक समय पूँजीवाद जनतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सरोकार रखता था लेकिन साम्राज्यवाद की अवस्था में इसका अधिकाधिक सरोकार अफसरशाही और सैन्यवाद से ही है। महान स्तालिन ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले सीपीएसयू की 19वीं कांफ्रेंस में कहा था कि पूँजीपति वर्ग ने उदार जनतंत्र के झण्डे को फेंक दिया है। आज हम देखते हैं कि संसदीय जनतंत्र असल में एक बेशर्म ढकोसले के सिवा और कुछ

14 अप्रैल को सीपीएम की पार्टी कांग्रेस में कॉमरेड प्रभाष घोष, साथ में बैठे हुए सीपीएम के महासचिव प्रकाश करात

नहीं है। बहुप्रचारित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक बहुत बड़ा धोखा है। लोगों की राय नहीं बल्कि पूँजीपति वर्ग का फैसला ही चुनाव में सब कुछ निर्धारित करता है। चुनाव के नाम पर पूँजीपति वर्ग अपने विश्वस्त राजनीतिक सेवक को चुनता है, सरकार में बैठा देता है, दुबारा सत्तासीन करता है और जरूरत पड़ने पर एक को हटा कर उसकी जगह दूसरे को गद्दी पर बिठाता है। पूँजीवादी जनतंत्र के बचे-खुचे अवशेष भी लुप्त हो चुके हैं। विभिन्न रूपों और विभिन्न आयामों में घोर फासीवाद अब लगभग तमाम विकसित और पिछड़े देशों में चलन बन गया है।

फासीवाद की तीन चारित्रिक विशेषताएं होती हैं–पूँजी का संकेन्द्रण या बढ़ता एकाधिकारीकरण, प्रशासनिक और

(शेष पृष्ठ 7 पर)

24 अप्रैल ....

(पृष्ठ 2 का शेष)

रहा है। इन सब जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोग एकजुट न हो पायें इसलिए उनको तरह-तरह से बांटने और जनतांत्रिक व श्रम अधिकारों में कटौती करने की भंयकर साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वोट या चुनाव से केवल सरकारें बदलती है नीतियां या व्यवस्था नहीं। शोषण-अन्याय ज्यूं का त्यों कायम रहता है। इसलिए क्राांति की चोट से ही पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना ही समस्या के समाधान का एकमात्र रास्ता है। इसके लिए भारत की क्रांतिकारी पार्टी एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) का ताकतवर होना निहायत जरूरी है। अंत में उन्होंने जनता से एस.यू. सी.आई.(कम्युनिस्ट) को मजबूत करने की अपील की। सभा को पार्टी के राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल ने भी संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता राज्य कमेटी सदस्य कॉ. उमा प्रसाद ने की। सभा की शुरूआत कॉ. शिवदास घोष पर रचित गीत के साथ हुई व समापन अन्तर्राष्ट्रीय गीत के साथ हुई। सभा मे भोपाल के कई जाने-माने प्रबुद्धजन भी मौजूद रहे।

कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती का भाषण

आज के सभापतिजी और सभी कॉमरेड्स, स्वाभाविक हैं कि कॉमरेड्स जानना चाहेगें कि हमारी पार्टी का सामाजिक परिस्थिति के बारे में क्या विश्लेषण है। पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर कामरेड्स जानना चाहेगें कि हम क्रांतिकारी पार्टी किसे कहते हैं और क्रांति की जरूरत भी क्या हैं और हमें क्रांति क्यों चाहिए । मैं इन सब बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। आज जब आम जनता के जीवन को तरह-तरह के संकटों ने घेर लिया है। आर्थिक संकट, राजनैतिक संकट, सामाजिक संकट, और सबसे बढ़कर सांस्कृतिक संकट विकराल रूप ले रहा है। लोग कह रहे हैं कि नरेन्द्र मोदी ये सब ठीक कर देंगे। कुछ दिन पहले बी.जे.पी. ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, क्या देश में महँगाई कम हो गई? क्या बेरोजगारी कम हो गई?, क्या हिन्दू-मुसलमान, बिहारी-बंगाली के बीच की लड़ाई खत्म हो गई? जो नौकरी करते हैं क्या उनकी नौकरी सुरक्षित हैं? बी.जे.पी. जितना कह रही हैं कि नरेन्द्र मोदी अच्छे दिन लायेगें, उतने ही बुरे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन किसके लिए? क्या आम जनता के लिए? बिल्कुल नहीं। देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है। शिक्षा पर हमला बढ़ रहा हैं। सांस्कृतिक स्थिति आप जानते हैं। महिलाएँ यहाँ बहुत उपस्थित हैं। महिलाओं पर हमला कई गुना बढ़ गया हैं। हर रोज आप टी.वी.-अखबार में देखते हैं। क्या कोई परिवर्तन हुआ? नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में कुछ नीतियाँ एकदम नग्न रूप से बड़े-बड़े पूँजीपतियों के लिए और आम लोगों के खिलाफ लागू की हैं। इस पर चर्चा करके समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग भली-भान्ति जानते हैं। तब इससे क्या पता चलता है। इससे सीधे पता चलता हैं कि सरकार बदलने से राजसत्ता नहीं बदल जाती। देश की स्थिति में परिवर्तन अपने आप नहीं हो जाता। स्थिति बदलने के लिये क्रांति चाहिए। क्रांति क्या है और क्रांति कौन ला सकता है आप को समझना पड़ेगा। क्रांति का मतलब है हथियारबंद क्रांति, चाहे वह भारत में हो, इग्लैड में, जापान में हो, फ्रांस में हो, किसी भी पूँजीवादी देश में हो। क्रांति का मतलब है मजदूर क्रांति, सर्वहारा वर्ग की क्रांति। इसके अलावा कोई और क्रांति नहीं हो सकती। सर्वहारा वर्ग की क्रांति का मायने क्या हैं यह आप को समझना पड़ेगा। हमारे देश में पूँजीवाद हैं, पूँजीवादी व्यवस्था है। पूँजीवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। पूँजीवाद का मायने है कि कुछ मुठ्ठी भर लोग जैसे कि टाटा-बिरला, गोयनका, अम्बानी-अडानी, ये सब उत्पादन के साधनों जैसे कि कारखानों, उद्योगों, बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिक हैं। कुछ मुठ्ठी भर आदमियों ने उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर रखा है और आम जनता चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, वह उद्योगों, खेतों या कार्यालयों में काम करने के लिये मजबूर हैं। यानी मालिक हमें नौकरी देते हैं, मजदूरी देते हैं, पैसे के बदले वे हमारी श्रम शक्ति को खरीदते हैं, हम अपनी श्रम-शक्ति को बेचते हैं। तब क्या दोनों के हित बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। टाटा और उसका मजदूर, दोनों के हित क्या एक हैं? नहीं। दोनों के हित भिन्न हैं केवल इतना ही नहीं बल्कि विरोधी भी हैं। जिसमें मालिक को मुनाफा होता है उसमें मजदूर को नुकसान है। यह मुनाफा कहाँ से आता है? मजदूर अपनी मेहनत से जो सम्पदा तैयार करते हैं, उस सम्पदा को अपनी जेब में रख लेते हैं। मुनाफे से पूँजी का पहाड़ मालिक के पास इक्कठा होता जाता हैं और मजदूर गरीब से गरीब होते रहने से गर्त में चला जाता है। ये है पूँजीवाद। क्योंकि इसमें उत्पादन सम्बन्ध मालिक-मजदूर का होता है। दूसरे, इसमें जो उत्पादन होता है, वह मालिक के मुनाफे के लिए। मुनाफे के बगैर मालिक उत्पादन नहीं करता। मुनाफा कैसे होता हैं? मजदूर अपनी श्रम-शक्ति बेचकर जो सम्पदा तैयार करते हैं उसे बाजार में बेचकर उत्पादन मालिक मुनाफा कमाते हैं। सम्पदा तैयार कर रहे हैं मजदूर और वही मजदूर गरीब से गरीब होकर बर्बाद हो रहे हैं। दुनिया भर में पूँजीवाद ऐसा ही है। पश्चिम बंगाल में माँ-बाप अपने बच्चे को बाजार में बेच रहे हैं। बच्चे को कौन बेच रहा है उसकी माँ। पूरे देश में भी स्थिति ऐसी ही है। सरकार बदलने से क्या होगा? पश्चिमी बंगाल में तो सी.पी.एम. पार्टी सत्ता में थी। वह जब सत्ता में आई, तब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब वहाँ तृणमूल का शासन है। क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। यह बिल्कुल सही है कि हम क्रांति चाहते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि क्रांति क्या होती है। क्रांति का मतलब है वर्तमान में जो स्थिति है, जो व्यवस्था है उसे एकदम आमूल परिवर्तित कर देना और बिल्कुल नयी स्थिति ला देना, ऐसी स्थिति जिसमें जो मजदूरी करेंगे वही मालिक होंगे, जो मालिक वही मजदूर और जो मजदूर वही मालिक होगा। मालिक और मजदूर में कोई अंतर नहीं रहेगा। अभी टाटा-बिड़ला कोई उत्पादन नहीं करता, उत्पादन करते हैं मजदूर और वही मजदूर मरते हैं भूखों। आज जो मकान बनाते हैं वे फुटपाथ पर सोते हैं। ये है पूँजीवाद। समाजवाद लाने के लिए चाहिए क्रांति। एक ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए जिसमें उत्पादन के तमाम साधनों पर पूरे समाज का मालिकाना होगा। यहाँ है व्यक्ति का मालिकाना, निजी मालिकाना और वहाँ होगा पूरे समाज का मालिकाना, सभी मजदूरों का मालिकाना, वहाँ जो मेहनत करेंगे वही खायेगें। यहाँ है उल्टा जो मेहनत नहीं करते वे खाते हैं और जो मेहनत कर रहा है वह भूखा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। इस व्यवस्था में इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह जो स्थिति है, यह जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें मालिक-मजदूर संबंध है, मुनाफे के लिए उत्पादन हो रहा है, जनता की जरूरतों के लिए नहीं। इसे कहते हैं हम पूंजीवाद, समाजवाद का उल्टा जहाँ तमाम उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का मालिकाना। किसी एक व्यक्ति का नहीं। वहाँ उत्पादन होता है जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए, समाज की जरूरतों के लिए उत्पादन, जैसे कि एक समय लेनिन व स्टॉलिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में हुआ था जैसे माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन में हुआ था, जैसे हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम में हुआ था। वैसा समाजवाद हमें अपने देश में चाहिए। हम कहेगें चाहिए-हाँ चाहिए लेकिन चाहने भर से क्या आ जायेगा? ये जो व्यवस्था है इसको चला रही है राज्यसत्ता, यह बात आपको गहराई से समझनी चाहिए। राज्यसत्ता क्या होती है? राज्यसत्ता होती है फौज व्यवस्था, नौकरशाही (प्रशासन-पुलिस व्यवस्था), न्याय व्यवस्था (न्यायपालिका)। ये चारों मिलकर पूंजीवाद की रक्षा कर रही हैं। यह व्यवस्था सरकार बदलने से नहीं बदलती। कॉमरेड शिवदास घोष ने यह सुन्दर ढंग से उदाहरण देकर समझा दिया है। एक कपड़ा मिल में कपड़ा बनता है, मिल को कोई भी चलाये उससे कपड़ा ही बनेगा। चाहे नरेन्द्र मोदी चलायें, मनमोहन सिंह चलायें, कम्युनिस्ट चलायें, कोई भी चलाये उससे कपड़ा ही बनेगा। यदि कपड़े की बजाय आपको कुछ और बनाना है तो पुरानी कपड़ा मिल को तोड़ना होगा। नयी मिल बनानी होगी। पुरानी मिल तोड़कर नया कुछ तथाकथित कम्युनिस्टों ने हमारे देश में किया हो ऐसा कुछ भी नहीं। पूंजीवाद में कोई भी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, बीजेपी, सी.पी.आई., सी. पी.एम., जनता दल (यू), जनता दल (एस), कोई भी हो सरकार में आकर इसी व्यवस्था को चलायेगा। इसलिए चुनाव से सरकार बदलती है राज्यसत्ता नहीं। राज्यसत्ता को उखाड़ फेंकना होगा क्रांति की ताकत से। गरीब किसान, खेत मजदूर, बटाईदार, कारखाना मजदूर, सफाई मजदूर ये सब पुरानी व्यवस्था की जगह पर नई व्यवस्था लाना चाहते हैं, इसे उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जरूरत पड़ने पर ये सब हथियार उठा लेते हैं, प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ये है क्रांति। क्रांति कोई मामूली बात नहीं है। क्रांति के बिना पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना संभव नहीं। लेकिन क्रांति लायेगा कौन? इसके लिए क्रांतिकारी पार्टी चाहिए, क्रांतिकारी पार्टी के बगैर क्रांति नहीं हो सकती। क्रांति से ही देश में पुरानी पूंजीवादी व्यवस्था व पूंजीवादी राज्यसत्ता का स्थान नई समाजवादी व्यवस्था व मजदूर राज्यसत्ता लेगी।

हमारे देश में ऐसी बहुत पार्टियां हैं, जैसे सी.पी.आई. , सी.पी.एम., नक्सल जो मार्क्सवाद-लेनिनवाद की बात करती हैं, क्रांति की बात करती हैं लेकिन यह अब साफ जाहिर हो गया है कि ये क्रांतिकारी पार्टियां हैं नहीं। पश्चिमी बंगाल में सी.पी.आई., सी.पी.एम. ने मिलकर राज्यसत्ता को संचालित किया। सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या बी.जे.पी. ने पश्चिमी बंगाल में तथाकथित कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई। इन दोनों में क्या अंतर है? ये सब एक ही हैं। इन सब ने पूंजीवादी व्यवस्था को ही मजबूत किया है।

इस शोषणमूलक व्यवस्था में आज हम क्या कर सकते हैं? हमारी पार्टी चाहती है कि जन आंदोलन बढ़े, जन आंदोलन तेज हो ताकि जनआंदोलन की ताकत से क्रांति शुरू हो जाये। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार बदलने से राज्यसत्ता नहीं बदलती। इसलिए कॉमरेड शिवदास घोष 1948 में बल्कि इससे पहले 1946 में ही समझ गये थे कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिसे कहा जाता है वह कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। ये तथाकथित कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी मार्क्सवाद-लेनिनवाद की बात करते हैं, इसे मानते हैं यह सब तो ठीक है लेकिन अपनी जिंदगी में वे इसे अमल में नही लाते हैं। सर्वहारा क्रांतिकारी संस्कृति को अपने जीवन में अमल में ना लाये तो कम्युनिस्ट नहीं बना जा सकता। सर्वहारा संस्कृति क्या होती है? ये जो पूंजीवादी संस्कृति है, व्यक्ति को आधार करके जो संस्कृति है वह पूंजीवादी संस्कृति है। व्यक्तिगत स्वार्थ, मेरा चिन्तन, मेरी सम्पत्ति, मेरा-मेरा यह सब जो है यह व्यक्तिवाद है, यह पूंजीवादी संस्कृति है। समाजवादी चिन्तन क्या है, हमारा-हमारा, आम जनता के हित के लिए जरूरत पड़ने पर हम प्राण भी दे देंगे, इसे हम सामाजिक चिन्तन कहते हैं, सर्वहारा का चिन्तन कहते हैं। मार्क्स ने जो दिखाया कि मजदूर अकेले-अकेले उत्पादन नहीं कर सकता। कारखाने में वे मिलकर काम करते हैं। जब उत्पादन होता है, सामूहिक रूप से होता है, समूह के लिए होता है। इसलिए सर्वहारा वर्ग का चिन्तन व सर्वहारा वर्ग की संस्कृति है सामूहिकतावाद। आपको यह गहराई से समझना चाहिए कि नई संस्कृति के बिना कुछ नया नहीं हो सकता। पुरानी संस्कृति को लेकर, व्यक्तिवादी चिन्तन को लेकर, अवसरवादी चिन्तन को लेकर आप समाजवाद लायेंगे यह कैसे होगा? भ्रष्टाचार का, व्यक्तिवाद का आज निकृष्ट रूप बुर्जुआ संस्कृति में दिखाई दे रहा है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं, मिल गई तो बनी रहेगी कि नहीं यह सब अनिश्चित है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है। आम लोगों की जिन्दगी की किसी को कोई चिन्ता नहीं है। ये मंत्री लोग जो भ्रष्टाचार में किस कद्र डूबे हुये हैं आज के अखबार में देखिये मध्य प्रदेश में किसानों को पांच करोड़ रुपया दिया गया। क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या बी.जे.पी. के राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होगा? भ्रष्टाचार पूरे देश में है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में यहाँ आज सब कुछ अनिश्चित है। जो आज पावर में हैं वे कुर्सी की ताकत से जेब भरने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी संस्कृति जो इसकी ठीक उल्टी है जिसमें सोचते हैं दूसरों की भलाई के लिए, सामूहिक विकास के लिए, खुद के लिए कुछ भी नहीं। सबकी मुक्ति में व्यक्ति की खुद की मुक्ति भी है। यह जो एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) भारत की एकमात्र सही कम्युनिस्ट पार्टी, सही क्रांतिकारी पार्टी है जो नई संस्कृति लेकर चल रही है जिसे कॉमरेड शिवदास घोष ने बनाया। इसलिए आप देखोगे जहाँ एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) का कैडर है, लीडर है, लोग कहते हैं वह आम आदमी से अलग है, उसका चिन्तन, आचरण, रहन-सहन व संस्कृति सब कुछ अलग

(शेष पृष्ठ 4 पर)

देश भर में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-बिल का विरोध

किसानों ने दिया धरना

गुना : धरने को सम्बोधित करते हुए कामरेड प्रताप सामल

गुना, मध्य प्रदेश : भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश में किसानों का विरोध जारी है। ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन द्वारा मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में इसका विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में गुना जिला मुख्यालय में किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में जिले के किसान शामिल हुए। कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया। गाँव-गाँव में नुक्कड सभाएं की गईं।

धरने में मुख्य अतिथि कृषक खेत मजदूर संगठन के मध्यप्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड उमा प्रसाद व मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी) पार्टी के राज्य सचिव कामरेड प्रताप सामल थे। कॉमरेड सामल ने कहा कि सरकार किसानों को समृद्ध करने व विकास व रोजगार का झांसा देकर उनकी जमीन छीनने का प्रयास कर रही है ताकि बडे-बड़े पूँजीपतियों को फायदा पहुँचाया जा सके, अगर वह वाकई किसानों को समृद्ध करना चाहती है तो उन्हें सस्ती दर पर खाद, बीज, बिजली उपलब्ध कराए, उनकी उपज का वाजिब दाम दे। उन्होंने कहा कि रोजगार एक झांसा है। जबकि सरकार पहले ही नई भर्ती पर रोक लगा चुकी है व सभी विभागों को ठेके पर देने की तैयारी कर रही है। संगठन के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड उमा प्रसाद ने किसानों से आन्दोलन तेज करने की अपील की एवं बड़ी संख्या में दिल्ली में 5 मई को किसानों की महारैली में शामिल होने का आह्वान किया।

धरने को पार्टी जिला सचिव कॉ. संदीप आर.बी. व लोकेश शर्मा ने भी सम्बोधित किया। धरने में किसानों की समस्याओं पर आधारित नाटक का भी मंचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन संगठन के राज्य सचिव कॉमरेड मनीष श्रीवास्तव ने किया।

उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

भिवानी : ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन(ऑल इण्डिया के.के.एम.एस.) और सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्यूनिस्ट) की ओर से 28 अप्रैल को हरियाणा के भिवानी, झज्जर, कैथल, कुरूक्षेत्र, सोनीपत, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ आदि कई जिलों में तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्तों/ तहसीलदारों की मार्फत भेजा गया।

ज्ञापन में कृषि भूमि अधिग्रहण पर मुकम्मल रोक लगाने, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश/बिल वापस लेने, बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों का 30,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने, गेहूँ पर 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने, किसानों के कर्जे माफ करने, फसल खराब होने पर मृतक किसान के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने, हर खेत को पानी और हर हाथ को रोजगार देने, सभी फसलों के लाभकारी दाम देने, फ्यूल चार्ज के नाम पर की गई 37 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि और दोनों बिजली वितरण निगमों द्वारा बिजली दरों में प्रस्तावित 15 प्रतिशत वृद्धि वापस लेने, भिवानी से तोशाम और तोशाम से हिसार रोड़ पर लगाया गया टोल टैक्स खत्म करने की मांग की गई।

भिवानी में प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के जिला उपप्रधान सुखबीर सिंह और एसयूसीआई(सी) के स्थानीय सचिव राजकुमार ने किया। ज्ञापन देने वालों में राजकुमार, सुखबीर सिंह, राजकुमार बासिया, धर्मवीर सिंह, सज्जन, मनीराम, संदीप, रंजत, छेलूराम, रामफल आदि कई किसान-मजदूर शामिल थे। तोशाम में ऑल इण्डिया के.के.एम.एस. और एसयूसीआई(कम्यूनिस्ट) की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम(नागरिक),तोशाम की मार्फत भेजा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के जिला प्रधान जिले सिंह और एसयूसीआई(सी) के स्थानीय सचिव रोहताश सिंह सैनी ने किया। ज्ञापन देने वालों में उम्मेद सिंह, फूल सिंह, वजीर सिंह, हवासिंह, मनोहर, आदि कई किसान-मजदूर शामिल थे।

कैथल की तहसील पुण्डरी में ऑल इण्डिया के.के.एम.एस. के जिलाध्यक्ष कॉ. बाबूराम के नेतृत्व में किसानों ने अध्यादेश की प्रतियां फूंक कर अपना रोष जताया। कुरूक्षेत्र की पेहवा अनाजमण्डी में एसयूसीआई (सी) के जिला सचिव कॉ. रोशनलाल व ऑल इण्डिया के.के.एम.एस. के कॉ. राजकुमार, रामसरूप व नंदलाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। अध्यादेश की प्रतियां फूंक कर किसानों ने इसके खिलाफ अपना रोष जताया।

सोनीपत में एसयूसीआई(सी)और ऑल इण्डिया के.के.एम.एस. के प्रतिनिधिमण्डल ने ज्ञापन सौपा। इस मौके पर एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव कॉ. ईश्वर सिंह राठी ने सभा को सम्बोधित किया।

रेवाड़ी में ज्ञापन देने वालों में एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव कॉ. राजेन्द्र सिंह, ऑल इण्डिया केकेएमएस के करतारसिंह, बलराम, कॉमरेड रवीन्द्र, शेरसिंह आदि शामिल थे। मण्डी अटेली में पुराना बस स्टेण्ड से तहसील तक जुलूस निकाला गया। इसमें एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव कॉ. ओमप्रकाश और ऑल इण्डिया केकेएमएस के कॉ. बलबीर सिंह के अलावा सुभाष, सीताराम, अमर सिंह, अभय सिंह, सूबेसिंह, गुरुचरण आदि शामिल थे।

मातनहेल में ऑल इण्डिया के.के.एम.एस. के जिलाध्यक्ष कॉ. अनूप सिंह व सचिव कॉ. करतार सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। अध्यादेश की प्रतियां फूंक कर किसानों ने इसके खिलाफ अपना रोष प्रकट किया।

बहादुरगढ़ में ऑल इण्डिया के.के.एम.एस. के जिलाध्यक्ष कॉ. जयकरण माण्डौथी, बलजीत, अशोक कुमार, राकेश, श्रीकिशन व ओमप्रकाश के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार की मार्फत प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा और अध्यादेश की प्रतियां फूंक कर अपना रोष जताया।

किसान नेताओं ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश/बिल के खिलाफ 5 मई को किसानों की दिल्ली में संसद पर महारैली में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने किसान-खेत मजदूरों का आह्वान किया।

कर्नाटक के किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन

कॉरपोरेट-परस्त और किसान-विरोधी भूमि-अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ कर्नाटक राज्य रयैत संघ के बैनर तले कर्नाटक के किसानों, दलितों और खेत मजदूरों ने 28 अप्रैल को विशाल विरोध प्रदर्शन किया और इसे निरस्त करने की मांग की।

कर्नाटक में सड़कों पर उतरे किसान

ऑल इण्डिया केकेएम.एस. केद्वारा ओडिशा में प्रदर्शन करते हुए किसान

24 अप्रैल.....

(पृष्ठ 2 का शेष)

है। क्यों अलग है? इसलिए कि वह नई संस्कृति है, सर्वहारा संस्कृति है, क्रांतिकारी संस्कृति है। जहाँ कहीं भी यह संस्कृति पहुँच रही है जनता की जनशक्ति बन रही है, वहीं एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) जनता की ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। यह कॉमरेड शिवदास घोष की महान सृष्टि है, महान संस्कृति है। इसलिए आप देखोगे हमारी पार्टी में विचार ऐसा बन रहा है कि कोई व्यक्ति हिन्दू हो या मुसलमान, बंगाली हो या बिहारी, मध्य प्रदेश का रहने वाला हो या गुजराती, पंजाबी या जो भी इन्सान समाज के लिए सोचता है वही अनुकरणीय है। विचार ऐसा नहीं हो रहा कि आपने किस परिवार में जन्म लिया। किसी व्यक्ति ने हिन्दू धर्म में, या मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म या बुद्ध धर्म में जन्म लिया तो क्या यह उसके हाथ में है। मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यह क्या मेरे हाथ में था? नहीं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जन्म लेने के बाद जब चिन्तन शुरू हुआ तो आपका चिन्तन क्या है, आपका विचार क्या है, आप सामाजिक प्रगति के लिए, समाज के विकास के लिए क्या भूमिका अदा कर रहे हैं –हम केवल इसी दृष्टिकोण से आपके बारे में विचार करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। कॉमरेड शिवदास घोष ने यह जो दृष्टिकोण दिया इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारी पार्टी का कैडर बिहार का हो या गुजरात का, मध्य प्रदेश का हो या बंगाल का, केरल का हो या कर्नाटक का, सभी का चिन्तन एक जैसा ही है। इस तरह एक नई संस्कृति, सर्वहारा संस्कृति, एक नये चिन्तन का जन्म पुराने समाज में हो रहा है। कॉमरेड शिवदास घोष ने देश में एक महान सृष्टि की है।

आज जब देश में हिन्दू-मुसलमान-बौद्ध-ईसाई को लेकर झगड़ा हो रहा है, बी.जे.पी. इस झगड़े को और आगे बढ़ा रही है। जनता कहीं एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने न लग जाये और कहीं इस व्यवस्था को बदल न डाले इसलिए उनकी चाल है लोगों की एकता को तोड़ो, उन्हें बांटकर रखो। इसके पीछे टाटा-बिड़ला का हाथ है यह आपको मूल में समझना होगा। साथियो, हमें एकताबद्ध होकर यह लड़ाई लड़नी होगी जिससे एक नई जनशक्ति का निर्माण होगा, हो भी रहा है जो पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर नई व्यवस्था का निर्माण करेगी। हम सब इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इस तरह आज की स्थिति की मैंने कुछ चर्चा की। देश की सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मंहगाई बढ़ रही है। नरेन्द्र मोदी के आने से पहले जितनी मंहगाई थी आज और भी ज्यादा बढ़ गई है। आर्थिक संकट बढ़ रहा है, जनता के जीवन में आने वाले समय में संकट और भी बढ़ जायेंगे। किसानों की आत्महत्यायें बढ़ रही हैं। छात्र-शिक्षित युवा भी आत्महत्या कर रहे हैं। अच्छे अंक मिलने के बावजूद युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। क्या ये सब मसले बी.जे.पी. आने के बाद, नरेन्द्र मोदी आने के बाद खत्म हुए? नहीं। बल्कि कई गुना बढ़ गये। इनको रोकने के लिए जितने नियम कानून बनाये जा रहे हैं ये उतने ही बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हजारों साल पुराने चिन्तन को लाया जा रहा है। गीता, वेद-पुराण को पाठ्यक्रम में लाया जा रहा है। ज्ञान-विज्ञान सब खत्म हो रहा है। शिक्षा रसातल में जा रही है। अब तक कांग्रेस पूंजीपतियों की सेवा करती आयी थी। अब बी.जे.पी. खुले रूप से उनकी बढ़-चढ़कर सेवा कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि पिछले चुनाव में जनता बी.जे.पी. को लाई। बी.जे.पी. की लहर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान में ही थी जहाँ वह पहले से सत्ता में थी। जनता बी.जे.पी. को इसलिए लायी कि कांग्रेस को हराना था। जहाँ बी.जे.पी. व कांग्रेस को हराने के लिए कोई अन्य पार्टी थी वहाँ बी.जे.पी. कुछ नहीं कर पाई। आंध्र प्रदेश और तैलंगाना में बी.जे.पी. कुछ नहीं कर पाई। बंगाल में ममता बनर्जी की तृण मूल कांग्रेस जीत गई। यह बात और स्पष्ट हो जाती है जब आप दिल्ली में देखोगे, जहाँ जनता कांग्रेस व बी.जे.पी. दोनों को हरा सकती थी उसने दोनों को हराया और केजरीवाल को वोट दिया।

यह है स्थिति। स्थिति भयंकर है जिसमें जीना मुश्किल है। इस स्थिति में जनांदोलन के अलावा लोगों के पास बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस जनांदोलन के लिए एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) लगातार प्रयासरत है। ऐसी वामपंथी पार्टियाँ, जैसे सी.पी.आई., सी.पी.एम., जिन्हें हम कम्युनिस्ट पार्टी नहीं मानते, फिर भी हम चाहेंगे कि वे भी जनांदोलन के लिए आगे आयें। उनके साथ मिलकर भी हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। यूनाइटेड आंदोलन, जनता का आंदोलन एक साथ मिलकर होना चाहिए। इस रास्ते से एक दिन हम क्रांति के रास्ते पर जायेंगे।

कॉमरेड्स, मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। महिलाओं पर हमले, जनता पर हमले, जनविरोधी नीतियाँ, यहाँ दूसरे राज्यों से कम नहीं हैं। यहाँ भी जनता आंदोलन के लिए तैयार है। जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर हमें आंदोलन करना है। यदि हम ऐसा कर सकें तो जनता तैयार है। वास्तविक स्थिति ऐसी ही है। जो पार्टी उन्हें सही नेतृत्व दे सकती है जनता उसका साथ देने को तैयार है। हमें नेतृत्व देना होगा। मैं कॉमरेडों से कहूंगा कि वे इस ढंग से अपने आपको तैयार करें ताकि वे जनता को समझा भी सकें और उन्हें आंदोलन में ला भी सकें। हम आंदोलन को सही दिशा में ले जा सकें। हमें इसी ढंग से तैयार होना है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुये जल्दी से जल्दी पार्टी को मजबूत करें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन। हमारे शिक्षक नेता कॉमरेड शिवदास घोष, लाल सलाम!

दिल्ली : एस.यू.सी.आई.(सी) दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी की ओर से 28 अप्रैल को चन्द्रशेखर आजाद कॉलोनी, किशनगंज में जनसभा की गई। नेपाल, बिहार यू.पी. में आए भूकम्प में मारे गए हजारों लोगों की याद में सभा से पहले 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर एसयूसीआई(सी) केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. छाया मुखर्जी मुख्य वक्ता थी। सभा की अध्यक्षता पार्टी के दिल्ली राज्य सचिव कॉ. प्राण शर्मा ने की। सभा को पार्टी की स्थानीय कमेटी सचिव व महिला सांस्कृतिक संगठन की दिल्ली राज्य सचिव कॉ. रितू कौशिक ने भी सभा को सम्बोधित किया।

अपने सम्बोधन में कॉ. छाया मुखर्जी ने 24 अप्रैल 1948 को एस.यू.सी.आई.(सी) के स्थापना सम्मेलन की ओर ले जाने के लिए पार्टी के संस्थापक महासचिव, इस युग के अन्यतम महान मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉ. शिवदास घोष ने अपने मुट्ठी भर सहयोद्धाओं को साथ लेकर जो कठिन और कष्टसाध्य संघर्ष किया था, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कॉमरेड घोष ने लेनिनवादी मॉडल की पार्टी बनाई। पश्चिम बंगाल के एक दूर-दराज के जिले से शुरू हुई यह पार्टी आज देश के 22 प्रान्तों में फैल चुकी है और पूँजीवादी शोषण-अत्याचार के खिलाफ लोगों को संगठित कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मोदी सरकार जो मीडिया के प्रचार के बल पर और कारपोरेट घरानों के द्वारा उभारे जाने से सत्ता में आई थी, तमाम जनसेवाओं का तेजी से निजीकरण करती जा रही है। इससे लोगों की दशा दयनीय होती जा रही है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह आरएसएस-बीजेपी गठजोड़ एक तरफ लोगों को लूटने के क्षेत्र एकाधिकारी पूँजीपतियों को प्रदान कर और दूसरी तरफ 'लव जेहाद' और घर वापसी जैसे नारों की आड़ में घोर हिन्दू साम्प्रदायिक मानसिकता को भड़काने के फासीवादी रास्ते का सहारा लेकर मरणासन्न पूँजीवाद को बरकरार रखने में मदद कर रही है। इसीलिए यह दकियानूसी पुरानी पौराणिक कहानियों को पाठ्यक्रम में लाकर लोगों में आधुनिक वैज्ञानिक सोच को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और मीडिया द्वारा पेश किया गया विकास के गुजरात मॉडल का गुब्बारा फट चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा यह बेतुकी दलील दी गई है कि अमीर और ज्यादा अमीर बनने से लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह सफेद झूठ है। केवल पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति ही लोगों को पूँजीवादी बंदिशों और लूट से निजात दिला सकती है। केवल इसी रास्ते उनकी समस्याएं हल हो सकती हैं। लेकिन क्रान्ति अपने आप नहीं होती है। उन्नत नीति-नैतिकता व संस्कृति के आधार पर आन्दोलन गठित करते हुए, जीवन के तमाम पहलुओं में संघर्ष करते हुए क्रान्ति की मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। जैसे सामंतवाद के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़कर एक समय पूँजीवाद उभर कर आया था, उसी

दिल्ली : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. छाया मुखर्जी

तरह एक नई समाजवादी संस्कृति, क्रान्तिकारी राजनीति और जोरदार आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन के आधार पर समाजवादी क्रान्ति हो सकती है। उन्होंने ऐसे आन्दोलन की लहर खड़ी करने की लोगों से अपील की।

वदोदरा: 24 अप्रैल एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) के 67वें स्थापना दिवस 24 अप्रैल के दिन यहाँ एक जनसभा की गई। पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. शंकर साहा सभा के मुख्य वक्ता थे। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने सारों वर्षों के बाद भी मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छात्रों-नौजवानों के जीवन में दुर्दशा बढ़ती ही जा रही है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, शहीद ए आजम भगतसिंह सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों और क्रान्तिकारियों द्वारा संजोए गए समाजवाद के सपने को आज के शासक चूर-चूर करते जा रहे हैं। लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार किसानों की जमीन जबरन छीन रही है ताकि पूँजीपति मुनाफा लूटने के लिए। यहाँ तक कि राममोहन राय, विद्यासागर महात्मा फूले, नर्मद आदि से शुरू हुआ नवजागरण का काम भी अधूरा पड़ा है। हमें ये दोनों ही काम पूरे करने होंगे। जनजीवन के ज्वलंत मुद्दों पर एक सतत जोरदार जनआन्दोलन के लिए आगे आने के लिए उन्होंने जनवादी और वामपंथी विचारों के नागरिकों से पुरजोर अपील की।

अन्य वक्ताओं में थे एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) के गुजरात राज्य कमेटी सचिव कॉ. द्वारिका नाथ रथ, पार्टी के वदोदरा जिला सचिव कॉ. तपन दासगुप्ता, पार्टी की राज्य कमेटी के सदस्य कॉ. प्रकाश भाई मेहता द्वारा पेश किए प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य कमेटी सदस्य कॉ. भारत भाई मेहता ने किया। जो सर्वसम्मति से पारित किया गया। सभा की अध्यक्षता राज्य कमेटी सदस्य कॉ. मीनाक्षी जोशी ने की।

भिवानी (हरियाणा) : मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश/बिल को रद्द कराने के लिए सोशलिस्ट यूनिटी सैन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) 5 मई को दिल्ली संसद पर होने जा रही किसान व खेतमजदूरों की महारैली को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग व समर्थन देगी।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस

मई दिवस विभिन्न राज्यों में रैली एवं सभाएं

सूरत में मई दिवस रैली को सम्बोधित करते हुए एसयूसीआई(सी) के पूर्व सांसद डॉ. तरुण मण्डल

सूरत (गुजरात): 1 मई की पूर्वसंध्या पर यहां एसयूसीआई(सी), ऑल इण्डिया यूटीयूसी और साऊथ गुजरात टैक्सटाइल वर्कर्स यूनियन की ओर संयुक्त रैली और विशाल जनसभा की गई। सभा के मुख्य अतिथि एसयूसीआई(सी) के पूर्व सांसद डा. तरुण मण्डल थे और मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी), गुजरात राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉ. द्वारकानाथ रथ थे। श्री गौतम ठाकेर, श्री कुशाभाई देसाई आदि जाने-माने लोग भी उपस्थित रहे और मजदूर आन्दोलन के पक्ष में बोले। डा. तरुण मण्डल ने पूंजीवादी उत्पादन और शोषण चक्र के बारे में बताया। अन्तराष्ट्रीय गीत के साथ सभा का समापन हुआ।

भिवानी : मई दिवस पर एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध भवन निर्माण कारीगर-मजदूर यूनियन, भट्ठा मजदूर एसोसियेशन, हरियाणा खेत मजदूर फैडरेशन आदि यूनियनों के बैनर तले मजदूर-कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकाल कर यहां 129वां अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। जुलूस दिनोद गेट से शुरू हुआ और सराय चौपटा, हांसी गेट, घण्टाघर होते हुए नेहरू पार्क में पहुंच कर सभा में तब्दील हो गया। सभा को एआईयूटीयूसी के राज्य कमेटी सदस्य रामफल, भवन निर्माण कारीगर-मजदूर यूनियन हरियाणा के जिला सचिव धर्मवीर सिंह, हरियाणा खेत मजदूर फैडरेशन के रोहताश ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता यूनियन के कोषाध्यक्ष राजकुमार ने की।

अन्तराष्ट्रीय मजदूर दिवस के गौरवमय इतिहास व महत्व को रखते हुए रामफल ने कहा कि मई दिवस मजदूरों के संघर्ष, कुर्बानी और एकता की उपज है। मजदूर आन्दोलन का अन्तिम लक्ष्य महज कुछ आर्थिक मांगें मनवा लेना या काम की शर्तों में कुछ सुधार करवाना ही नहीं है बल्कि पूंजीवादी शोषण से मुक्ति पाना है। यह केवल मजदूरों की ही नहीं, बल्कि समूची मानवता की मुक्ति का रास्ता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य में सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार ने मजदूरों पर भयंकर हमला बोल दिया है। यह सरकार भी निजीकरण-उदारीकरण-भूमंडलीकरण की वही विनाशकारी नीतियां तेजी से लागू कर रही हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में शुरू की गई थी। मजदूरों की छंटनी, लूट और ठेकाकरण की बेलगाम ताकत मालिकों को देने के लिए औद्योगिक विवाद कानून, फैक्ट्री(एमेण्डमेंट) बिल 2014, कॉण्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन और एबोलिशन) एक्ट, एप्रन्टिस(एमेण्डमेंट) बिल 2014 आदि श्रम कानूनों में मजदूर-विरोधी संशोधन किये जा रहे हैं। मजदूरों के साथ-साथ किसान-खेतमजदूरों की रोजी-रोटी छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का काला फरमान जारी कर दिया है। श्रमिकों की पुरानी पेन्शन स्कीम बंद कर दी है। सरकार मजदूर-कर्मचारियों की कष्ट कमाई से जमा ईपीएफ को भी शेयर बाजार में निवेश करने जा रही है। यूनियन बनाने व हड़ताल करने के बड़े संघर्षों से हासिल जनतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। वक्ताओं ने इन सभी प्रस्तावित मजदूर-विरोधी 'संशोधनों' को निरस्त करने की मांग की। उन्होंने मजदूर आन्दोलन को अर्थवाद, अवसरवाद व सामाजिक जनवाद की घातक प्रवृत्तियों से मुक्त करने पर जोर दिया।

यूनियन के जिला सचिव धर्मवीर सिंह ने कहा कि सभी भवन निर्माण मजदूर-कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन पंजीकरण व हितलाभ पाने की प्रक्रिया जटिल होने से बहुत ही कम श्रमिकों का पंजीकरण हो पाया है। ज्यादातर मजदूर-कारीगर इन थोड़ी-बहुत कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हैं। श्रमिकों को हितलाभ देने से टालमटोल करने के लिए बेतुकी शर्तें और अनावश्यक कागजी कार्रवाइयां थोंपी जा रही हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड का बुनियादी ढांचा और पर्याप्त स्टाफ नहीं है। कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। बोर्ड के कोष में सैकड़ों करोड़ रुपये जमा हैं जबकि मजदूरों के लिए खर्च बहुत ही कम किये गये हैं। भ्रष्टाचार व्याप्त है। मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। सुन्दर कोठी-बंगले बनाने वालों के पास रोटी, कपड़ा, मकान तक नहीं है। वे शिक्षा व इलाज की सुविधा से वंचित हैं। उन्होंने सरकार की इन मजदूर-विरोधी नीतियों व कदमों के खिलाफ आन्दोलन गठित करने की अपील की।

सभाध्यक्ष राजकुमार ने कहा कि कारीगर-मजदूरों को पूरे साल काम नहीं मिलता है। मजदूरों की दिहाड़ी मार ली जाती है। मारी गई दिहाड़ी दिलाने का कोई तंत्र ही नहीं है। ठेकेदारों व मालिकों द्वारा श्रम कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज 8 घण्टे कार्य दिवस को मान्यता होने पर भी संगठित-असंगठित क्षेत्र में इसकी पालना नहीं हो रही है। 12-12 घण्टे काम लिया जाता है। मजदूरों को वेज स्लिप, पहचान पत्र, हाजरी रजिस्टर में मजदूरों के नाम, ई.एस.आई. व पी. एफ. जैसे अनिवार्य कानूनी प्रावधान भी लागू नहीं हैं। महंगाई आकाश छूती जा रही है। बेरोजगारी विकराल रूप लेती जा रही है। हालात असहनीय हैं। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, नई नौकरियां सृजित करने, खाली पड़े पदों पर स्थायी नियुक्ति करने, 15वें श्रम सम्मेलन व सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन 15000 रुपये महीना देने, खेतमजदूरों सहित सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने, स्कीमों में कार्यरत कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा व सामाजिक सुरक्षा देने, मनरेगा के तहत कम से कम 300 रुपये रोजाना दिहाड़ी देने और श्रम कानूनों की सख्ती से पालना करने आदि मांगों के लिए आवाज बुलन्द की गई।

रेवाड़ी (हरियाणा) : 1 मई को रेवाड़ी के राव तुलाराम पार्क में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर एक संयुक्त सभा की गई जिसमें शिकागो के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और मई दिवस से प्रेरणा लेकर आन्दोलन मजबूत करने की शपथ ली गई।

सभा को मुख्य रूप से केन्द्रीय ट्रेड यूनियन ऑल इण्डिया यू.टी.य.सी. के जिला रेवाड़ी के सलाहकार कॉ. राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने बात रखी। उन्होंने मजदूरों को एकजुट होने व अपने आन्दोलन की पूँजीवाद-विरोधी दिशा देने का आह्वान किया।

सभा में सीटू के नेता कॉ. राजसिंह, एआईयूटीयूसी के जिला प्रधान कॉ. बलराम, कर्मचारी नेता हरिसिंह मुलोदिया, किसान नेता कॉ. रामकुमार, आंगनवाड़ी कर्मचारी व सहायिका यूनियन की श्रीमती राजेश, मिड डे मील यूनियन की नेता श्रीमती मुन्नी देवी, समाजसेवी प्रो. अनिरुद्ध यादव, संयुक्त ट्रेड यूनियन कमेटी, बावल के एक्जाइड के प्रधान सतपाल, महासचिव प्रधान राजकुमार, हीरो मोटर्स धारूहेड़ा यूनियन के प्रधान राजेन्द्र सिंह, महेन्द्र आदि वक्ताओं ने बात रखी। सभा में विभिन्न यूनियनों के हजारों मजदूर-कर्मचारियों एवं महिलाओं ने भाग लिया। दो मिनट का मौन धारण करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।

इलाहाबाद (उ.प्र.) : ऐतिहासिक मई दिवस के अवसर पर 2 मई 2015 को में ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेन्टर (एआईयूटीयूसी) की इलाहाबाद इकाई की ओर से मई दिवस का इतिहास और आज उसकी प्रासंगिकता विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें उ.प्र. आंगनवाड़ी एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्षा कॉ. लता शर्मा ने मई दिवस के इतिहास पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज मजदूर-कर्मचारियों की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। लम्बे संघर्षों के माध्यम से हासिल किए गये मजदूर अधिकार एक-एक कर छीने जा रहे हैं, ऐसे में सशक्त मजदूर आन्दोलन समय की जरूरत है और इसीलिए मई दिवस आज ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। बतौर मुख्य वक्ता बोलते हुए एस.यू.सी.आई.(सी) उ.प्र. राज्य समिति सदस्य कॉ. स्वप्न चटर्जी ने कहा कि पूंजीवाद के विकास की स्थिति खत्म हो चुकी है और यह आज संकटग्रस्त होकर प्रतिक्रियावादी हो गया है। इसलिए सभी जनवादी अधिकारों को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की संकटग्रस्त अवस्था में कर्मचारी-मजदूर आन्दोलन को कुछ आर्थिक मांगों के दायरे से ऊपर उठते हुए समाज परिवर्तन के आन्दोलन में बदलना होगा। गोष्ठी में बात रखते हुए कॉ. ओम प्रकाश ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने की जरूरत पर बल दिया। गोष्ठी को कॉ. रामयश, घनश्याम मौर्य, सेवानिवृत्त कर्मचारी बब्बन राम, नीलम शर्मा, राजेश व राजवेन्द्र सिंह ने भी सम्बोधित किया। गोष्ठी का संचालन एआईयूटीयूसी के राज्य समिति सदस्य कॉ. निर्मल कुमार मिश्र ने किया। गोष्ठी में विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों सहित भवन निर्माण श्रमिक सावन, सेवानिवृत्त कर्मचारी नेता कॉ. एस.पी.रजक, एम.ई.एस. के बांकेलाल, आरिफ खान, ए.जी. ऑफिस के टिग्गा व मिश्रीलाल भी शामिल हुए।

24 अप्रैल .....

(पृष्ठ 4 का शेष)

भिवानी : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. सत्यवान

यह घोषणा 24 अप्रैल, 2015 को पार्टी के 67वें स्थापना दिवस पर राजपूत धर्मशाला भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय जनसभा में की गई। आगामी 28 अप्रैल को कृषक खेत मजदूर संगठन के साथ मिल कर पार्टी कार्यकर्ता तहसील स्तर पर भाजपा सरकार के काले कारनामों और लोगों के हितों की अनदेखी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और अधिकारियों को ज्ञापन देकर बिजली दरों में प्यूल चार्ज के नाम पर की गई 37 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश/बिल वापस लेने की मांग करेगी। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि व तेज हवाओं से उजड़ी फसलों का 30 हजार रुपये प्रति एकड़ व मृतक किसान परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने, गेहूं पर 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने व कर्ज माफी की मांग को जोरदार ढंग से उठाया जाएगा।

जनसभा में मुख्य वक्ता पार्टी की केन्द्रीय कमेटी सदस्य एवं हरियाणा राज्य कमेटी के सचिव सत्यवान ने जनजीवन के प्रमुख सवालों पर खुल कर चर्चा की। अधयक्षता राजय कमेटी के वरिष्ठ सदस्य अनूप सिंह ने की और संचालन पार्टी के भिवानी जिला सचिव रामफल ने किया। अन्य वक्ता राज्य कमेटी सदस्य एवं रिवाड़ी जिला कमेटी के सचिव राजेन्द्र सिंह रहे।

मुख्य वक्ता सत्यवान ने कहा कि कांग्रेस की तरह भाजपा भी बड़े पूंजीपतियों, एकाधिकारी घरानें की सेवादार बन कर लोगों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। 'अच्छे दिन' देशी-विदेशी शोषक पूंजीपतियों, मुनाफाखोरों के आये हैं। मजदूर-किसानों, कर्मचारियों व अन्य तबकों के मेहनतकशों को तो कड़वी दवा पिलाई जा रही है। बेमैसम बारिश से खराब हुई फसलों का सरकार मुआवजा नहीं दे रही है, केवल नाटकबाजी व घोषाओं तक सीमित है। हर क्षेत्र में विदेशी पूंजी (एफडीआई) को न्यौता दे रही है। कृषि सब्सीडी व स्वास्थ्य बजट, शिक्षा बजट आदि में भारी कटौती कर दी है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी विकराल रूप ले चुकी है। शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी, परिवहन इतने महंगे हैं कि लोगों की पहुंच से बाहरहोते जा रहे हैं। अपराधों की कोई रोकथाम नहीं है। छात्राओं, बच्चियों , महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, गैंग रेप बढ़ रहे हैं। युवाओं को नशे में डुबोया जा रहा है। इसके खिलाफ लोगों के विरोध की आवाज को कमजोर करने के लिए धर्म, भाषा, ग्रंथ, जाति आदि की आड़ में समाज में फूट डाली जा रही है। जनतांत्रिक अधिकारों व श्रम अधिकारों में कटौती की जा रही है। खुद को जनसेवक बताने वाले भाजपा नेता-मंत्री जनता से भारी वादाखिलाफी और विश्वासघात कर रहे हैं। मोदी व खट्टर सरकार शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था का पोषण कर रहे है। पार्टी नेताओं ने कहा कि इससे मुक्ति वैज्ञानिक समाजवाद से ही सम्भव है। वामपंथ ही एकमात्र कारगर विकल्प है। उन्होंने वामपंथी पार्टियों व संघर्षशील ताकतों को साझे आन्दोलनों में भागीदारी का न्यौता दिया ताकि फासीवादी ताकतों को रोका जा सके। भाजपा के शासन में आने पर ये फासीवादी ताकतें हर रोज बेरोकटोक बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं और समाज में धार्मिक कट्टरता, अन्धविश्वास और साम्प्रदायिंक वैमनस्य फैला रही हैं। पार्टी ने शिक्षा के व्यापारीकरण, सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक बेरोकटोक पास करने की गलत नीति, स्वास्थ्य बजट में कटौती, भूमि अधिग्रहण, श्रम अधिकारों में कटौती आदि

के खिलाफ प्रदेशव्यापी जोरदार अभियान चलाने और वैज्ञानिक सोच-समझ को जनमानस तक ले जाने का आह्वान किया।

रॉंची, झारखण्ड : 26 अप्रैल को एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर रॉंची के सैक्टर-03, धुर्वा स्थित जवाहर एकेडमी में एक जनसभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) के झारखण्ड राज्य सचिव रबीन समाजपति ने किया। सभा के मुख्य वक्ता के रूप में एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के सैण्ट्रल कमेटी की ओर से उपस्थित शंकर दासगुप्ता ने कहा कि आज हम यह दिवस ऐसी स्थिति में मना रहे हैं जब केन्द्र व झारखण्ड राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्राहि-त्राहि कर रही है। आज पूरे देश की जनता लगातार बेलगाम हो रही महंगाई की मार झेल रही है। हर रोज हम टीवी, समाचारपत्रों में नारी पर हो रहे अत्याचार की खबरें देख और सुन रहे हैं। शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी मौलिक आवश्यकताओं को भी जनता की पहुँच से दूर कर व्यापार में तब्दील किया जा रहा है। पानी, बिजली, सड़क की अवस्था भी अत्यंत ही दयनीय हो गई है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान करना तो दूर, सरकार भूमि अधिग्रहण बिल के जरिए गरीब किसानों से उनकी जमीन छीनने की तैयारी में है। शिक्षा का निजीकरण व व्यापारीकरण कर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। शराब की दुकानों को धड़ल्ले के साथ लाईसेंस दिये जा रहे हैं और साथ ही सिनेमा, साहित्य व इण्टरनेट के जरिए सैक्स और हिंसा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आज झारखण्ड के 45 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। देश में प्रति व्यक्ति आय 74,920 रुपये है लेकिन झारखण्ड में मात्र 37000 रुपये। राज्य के 97 लाख लोग निरक्षर हैं। 90 लाख लोग बेरोजगार हैं। हर वर्ष हजारों की संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मौत की गोद में सो जाते हैं। झारखण्ड की स्थापना के दौरान इस राज्य का बजट सरप्लस था लेकिन आज हमारा राज्य 34,868 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन आज तक झारखण्ड में बनी किसी भी पार्टी की सरकार ने इन समस्याओं को दरकिनार कर और पार्टीगत मतभेदों को भुलाकर सभी मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कई बार विधानसभा में पास कराया गया है। वर्तमान में भी सरकार देशी-विदेशी कोरपोरेट घरानों के फायदे के लिए राज्य की खनिज-सम्पदा, जल व अन्य प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की योजनाएं तैयार कर रही है। स्थानीय के नाम पर सरकार राज्य के आदिवासी-मूलवासियों के कल्याण की जगह उन्हें गुमराह

मुम्बई में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड छाया मुखर्जी

करने का प्रयास कर रही है।

वास्तविकता यह है कि सरकार चाहे किसी की भी बने, उससे आम जनता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह पूँजीवादी व्यवस्था है और इसकी बागडोर देश के बड़े-बड़े पूँजीपतियों के हाथ में है। यह पूँजीवाद का नियम ही है कि जब देश की आम जनता किसी एक राजनीतिक पार्टी की सरकार से असंतुष्ट नजर आने लगती है तो यही पूँजीपति वर्ग किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी की सरकार बनवा देता हैं। कांग्रेस एवं भाजपा ही नहीं बल्कि झामुमो, आजसु एवं झाविसो जैसी क्षेत्रीय पार्टियाँ भी उन्हीं पूँजीपतियों के हाथों की कठपुतली हैं। देश के बड़े-बड़े पूँजीपति इन सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के वक्त करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं और ये राजनीतिक पार्टियाँ भी उनके प्रति अपनी वफादारी बखूबी निभाती हैं। जब इनमें से किसी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इनकी सरकार सिर्फ इन्हीं पूँजीपतियों के फायदे के लिए हर प्रकार के काम करती है। नतीजतन ये सरकारें पेट्रोल, डीजल से लेकर आम जनता की रोजमर्रा की आवश्यकताओं की वस्तुओं की कीमतें मनमाने रूप से बढ़ाती हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है देश की आम गरीब जनता को। झारखण्ड राज्य अलग होने के बाद भी आज जनता की ऐसी दुर्दशा होने के पीछे भी यही कारण है कि हर बार सरकार बनने के बाद ये पार्टियाँ मूकदर्शक बन कर बैठी और पूँजीपति वर्ग जनता का शोषण कर और भी ज्यादा पैसे कमाते रहते हैं। वर्तमान समय की भाजपा सरकार भी यही काम कर रही है। इन समस्याओं से निजात किसी चुनावी दलदल में फंसकर संभव नहीं हैं। यह तभी संभव है जब आम जनता को गोलबंद कर सरकार की तमाम जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हर गली, मौहल्लों, स्कूल व कॉलेजों में जनकमेटियाँ गठित की जाएं और व्यापक स्तर पर एक संगठित व सशक्त जनान्दोलन तैयार कर इस पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की मुहिम को और भी तेज किया जाए। हमारी पार्टी एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) लगातार देश भर में जन-जीवन की ज्वलंत सवालों को लेकर शक्तिशाली जनान्दोलन चला रही है और आज हमें भी पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को वर्तमान जटिल परिस्थिति का विश्लेषण कर अपने संघर्ष की दिशा तय करने और मंजिल तक पहुँचाने का प्रण लेना चाहिए।

मुम्बई: 67वे स्थापना दिवस पर एस.यू.सी.आई.(सी) की मुम्बई सांगठनिक कमेटी द्वारा 25 अप्रैल को समता विद्या मन्दिर (स्कूल) पाइप लाइन, मोहली गाँव, साकी नाका, घाटकोपर-अंधेरी रोड, मुम्बई में जनसभा की गई। यवतमाल, ठाणे, रायगढ़ जिलों और मुम्बई, नवी मुम्बई आदि इलाकों से सैकड़ों लोगों ने सभा में शिरकत की। सभा की अध्यक्षता पार्टी की मुम्बई सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉ. अनिल त्यागी ने की। सभा की मुख्य वक्ता पार्टी की केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. छाया मुखर्जी ने दिखाया कि कैसे उस समय कम्युनिस्ट पार्टी नामधारी पार्टी होने के बावजूद 24 अप्रैल 1948 को देश की एकमात्र क्रान्तिकारी पार्टी एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) की स्थापना कॉ. शिवदास घोष ने की। मौजूदा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार की निन्दा करते हुए शिक्षा में मुस्लिमों का 5% आरक्षण घटाने और गौमांस पर रोक लगाने के महाराष्ट्र राज्य की फड़नवीस-नीत बीजेपी-शिवसेना सरकार के कदम को साम्प्रदायिकता फैलाने की चाल करार दिया।

भुवनेश्वर (ओडिशा) : एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के 67वें स्थापना दिवस पर ओडिशा में भुवनेश्वर में 26 अप्रैल को राज्य स्तरीय जनसभा हुई। इस अवसर पर पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. सौमेन बसु मुख्य वक्ता थे। राज्य सचिव कॉ. धुर्जटी दास ने सभा की अध्यक्षता की।

हमें एकता चाहिए ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

अफसरशाही की शक्ति का संकेन्द्रण और देश के लोगों की सोच और संस्कृति के क्षेत्र में अध्यात्मवाद और विज्ञान के तकनीकी पहलओं का सम्मिश्रण करने के जरिए चिन्तन का रेजिमेण्टेशन यानी यांत्रिक और एक सांचे में ढली हुई चिन्तनपद्धति का विस्तार। फासीवाद के ये तीनों लक्षण हमारे देश में मौजूद हैं। शासक पूँजीपति वर्ग की जरूरत के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जगह बीजेपी को लाया गया। बीजेपी एक तरफ बेरहम पूँजीवादी आर्थिक शोषण और भीषण राजनीतिक दमन को जारी रखने तथा इसे और भी तीव्रतर करने के लिए प्रतिबद्ध है और दूसरी तरफ हमारे देश में जारी फासीवादीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शायद आप जानते हैं जब गत शताब्दी की तमाम महान विभूतियों जैसे रोमां रोलां, आइनस्टीन, बर्नार्ड शॉ, रवीन्द्रनाथ और अन्य हस्तियों द्वारा जब फासीवादी हिटलर की निन्दा की गई थी तब भारत में ये संघ परिवार के 'गुरुजी' या सिद्धांतकार एमएस गोलवलकर ही थे जिन्होंने हिटलर की प्रशंसा की थी और कहा था कि हिटलर ने यहूदियों को खदेड़ कर जर्मन नस्ल का शुद्धिकरण करके भारत में हिन्दुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाए इसका रास्ता दिखाया है। गोलवलकर ने भारतीय नवजागरण और स्वतंत्रता संग्राम की आलोचना की थी क्योंकि यह हिन्दू राष्ट्रवाद आधारित संघर्ष नहीं था और केवल ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध संचालित था। बीजेपी उसी परम्परा की वारिस है। इसने विचारधारा और संस्कृति के क्षेत्र में भयंकर हमला बोल दिया है। ये पुराने दकियानूसी मध्ययुगीन धार्मिक विचारों और संस्कृति को पुनर्जीवित, रेखांकित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे हास्यास्पद दावा करते हैं कि तमाम आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान प्राचीन हिन्दू भारत में खोज लिया गया था। वे विज्ञान की जगह पौराणिक कहानियों को ला रहे हैं, इतिहास को तोड़मरोड़ रहे हैं और तदनुसार स्कूली पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम को भी फिर नये सिरे से लिखा जा रहा है। इसका उद्देश्य है हिन्दू अंधराष्ट्रवाद, पुरातन परम्परावाद को उकसाना और वैज्ञानिक मनन और तर्कबुद्धि को तबाह कर अंधविश्वास को पनपाना। यह एक बहुत ही खतरनाक हमला है। दूसरी तरफ वे जन-संघर्षों के विकास को बाधित करने और हिन्दू वोट बैंक तैयार करने के लिए शोषित लोगों को धार्मिक विश्वास के आधार पर बांटने के लिए साम्प्रदायिक दंगे-फसाद भड़का और करवा रहे हैं। यह उनका घृणित षड्यंत्र है।

इसके अलावा पूँजीवाद के स्वार्थ में वे तमाम मानवीय मूल्यबोधों और नीति-नैतिकता को तबाह करने के लिए संस्कृति के क्षेत्र में हमले कर रहे हैं। वे युवा पीढ़ी की नैतिक रीढ़ को तोड़ रहे हैं। वर्तमान में ये जो छेड़खानी, बलात्कार सामूहिक बलात्कार हत्या और यहाँ तक कि बच्चियों और बूढ़ी औरतों पर बलात्कार निरन्तर और तेजी से बढ़ रहे हैं यह कोई संयोग नहीं है। क्या यह वही देश है जहाँ एक समय राम मोहन, विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, रवीन्द्रनाथ, शरत्चन्द्र, प्रेमचन्द, सुब्रमण्यम भारती पैदा हुए थे? यह देश को पूरी तरह मटियामेट किया जा रहा है। यह हमारे देश का अंधकारमय दौर है।

यह भी गौरतलब है कि एक उभरती साम्राज्यवादी ताकत होने के नाते भारतीय राजसत्ता अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ हाथ मिला कर चल रही है। दक्षिण एशिया, हिन्द महासागरीय राज्यों, मध्य-पूर्व, अफ्रीका और अन्य देशों में भारतीय प्रभुत्व को विस्तारित करने के अपने प्रयास में अमेरिका के साथ और भी घनिष्ट आर्थिक, राजनैतिक, सामरिक सम्बन्ध विकसित कर रही है ताकि वित्तीय पूँजी और सामानों का अधिक निर्यात किया जा सके। साथ ही साथ भारत ब्रिक्स (बीआरआईसीएस) गठजोड़ के साथ भी सम्बन्ध बनाए हुए है ताकि अमेरिका के साथ मोल-भाव की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसलिए परिस्थिति मांग करती है कि आज भारतीय शासक वर्ग और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ सशक्त, दीर्घ स्थाई, जुझारू वाम और जनवादी आन्दोलन संगठित किया जाए और इसके साथ-साथ बीजेपी और आरएसएस के सैद्धांतिक-सांस्कृतिक खतरनाक हमले को रोकने के लिए सशक्त सैद्धांतिक और सांस्कृतिक संघर्ष छेड़ा जाए।

वामपंथी एकता के सवाल पर कॉमरेड प्रकाश करात के साथ मैं सहमत हूँ लेकिन यहाँ एक बिन्दु बहुत महत्त्वपूर्ण है, इसे मैंने सीपीआई की पार्टी कांग्रेस में भी उठाया था। कौन वामपंथी हैं, कौन धर्मनिरपक्ष हैं और कौन जनवादी हैं? इस विषय में लोगों के बीच बहुत भ्रान्ति है। इसके बारे में समझदारी में कोई अस्पष्टता या घालमेल नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं जो पार्टियाँ खुद को मार्क्सवादी मानती हैं भले ही इसकी समझदारी और इसे लागू करने के बारे में उनके बुनियादी तफर्क हों उन्हीं को वामपंथी माना जाना चाहिए। कांग्रेस जैसी पार्टियाँ और अन्य क्षेत्रीय, संकीर्ण, जातिवादी दल और गठजोड़ जो चुनावों में बीजेपी का विरोध करती हैं इसका मायना जरूरी नहीं कि वे धर्मनिर्पेक्ष और जनवादी हैं। धर्मनिरक्षता की अवधारणा पश्चिम से आई थी जो ऐतिहासिक तौर पर पश्चिमी नवजागरण और बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति के दौरान उभरी थी। दार्शनिक तौर पर धर्मनिरपेक्षता का मायना किसी भी अतिप्राकृतिक सत्ता को मान्यता न देना और सिर्फ प्रकृति और वास्तविकता के तौर पर भौतिक जगत को मान्यता देना है। राजनैतिक तौर पर धर्मनिरपेक्षता का मायना है राजसत्ता के संचालन, राजनैतिक मामलों, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र को धार्मिक क्रियाकलापों से मुक्त रखा जाना चाहिए। राजसत्ता न तो किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगी, न ही धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करेगी। धर्म व्यक्तिगत विश्वास का मामला रहना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रान्ति से भयभीत होने के चलते राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग ने न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ राजनैतिक तौर पर समझौता किया बल्कि इसने सैद्धान्तिक और सांस्कृतिक तौर पर धर्म के साथ भी समझौता किया और सभी धर्मों को प्रोत्साहन के रूप में धर्मनिरपेक्षता की वकालत की जो दरअसल छद्म धर्मनिरपेक्षता है। जनवादी पार्टियाँ वे हैं जो धर्मनिरपेक्ष जनवादी मूल्यों को मानती हैं, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, संकीर्णतावाद का विरोध करती हैं। साम्राज्यवाद का सतत विरोध करती है और वामपंथ का समर्थन करती हैं तथा चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में मेहनतकश लोगों के जनवादी संघर्षों को प्रोत्साहित करती है। वाम, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी एकता के नाम पर सिर्फ चुनावी फायदों पर नजरें गड़ा कर कोई खिचड़ी गठजोड़ नहीं हो सकता है।

मुझे याद आता है कि आजादी के ठीक बाद हमारे देश में वाम आन्दोलन का शानदार दौर रहा है। उन संघर्षों में बहुतों ने अपना खून बहाया और शहीद हो गए। उस समय वामपंथियों को ही कांग्रेस का एकमात्र विकल्प माना जाता था। उन दिनों आजादी आन्दोलन में वामपंथी धारा की निरन्तरता में ही वामपंथी आन्दोलन विकसित हुए थे और महान स्तालिन तथा महान माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में जोरदार विश्व साम्यवादी आन्दोलन द्वारा और भी मजबूत हुए थे। लेकिन आज हालात बिलकुल बदल गए हैं। एक तरफ वामपंथियों ने हमारे देश में एक के बाद एक बड़ा भारी भटकाव और खतरनाक गलती की है जिससे लोगों के बीच अविश्वास और भ्रान्तियाँ पैदा हुई। दूसरी तरफ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूँजीपति वर्ग के एजेण्टों के रूप में संशोधनवादियों ने स्तालिन पर हमला बोल दिया था न सिर्फ उनकी अथोरिटी को खत्म करने के लिए बल्कि लेनिन की अथोरिटी को भी कम करने के लिए और इस प्रकार पूँजीवाद की पुनः बहाली की तथा समाजवाद के ध्वंस की जमीन तैयार कर दी।

लेकिन यह खुशी की बात है कि पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन और पूर्वी यूरोप में हजारों हजार लोग प्रदर्शनों में लेनिन और स्तालिन की तस्वीरें लिए हुए और समाजवाद की बहाली के नारे बुलन्द करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं। साथ-साथ यह भी उल्लेखनीय है कि पूँजीवाद को संकट से बचाने पर लक्षित भूमण्डलीकरण की स्कीम ने उलटे संकट को भूमण्डलीय स्तर पर और भी गहरा कर दिया है। विश्व साम्राज्यवाद-पूँजीवाद लगभग एक दशक से भी ज्यादा समय से अभूतपूर्व मंदी में है और यह कहा जा सकता है कि अब जिन्दा रखने के लिए वेण्टीलेटर पर है। ऐसा कोई डाक्टर नहीं है जो पूँजीवाद की बीमारी का इलाज कर सके। बाजार अर्थव्यवस्था निरन्तर सिकुड़ते बाजार संकट का सामना कर रही है। अभूतपूर्व रूप से लोगों का गुस्सा फूट पड़ रहा है। अमेरिका, यूरोप और सभी जगह जन संघर्षों का सैलाब स्वत:स्फूर्त रूप से उमड़ रहा है। लोग नेतृत्व के लिए पुकार रहे हैं। क्रान्ति की वास्तविक जमीन यानी वस्तुगत परिस्थिति तैयार है। सब्जेक्टिव परिस्थिति यानी महान मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन-स्तालिन-माओ त्से तुंग की क्रान्तिकारी शिक्षाओं से लैस सर्वहारा पार्टियों का देश-देश में उभर कर आना बाकी है। इतिहास के नियम के मुताबिक देर-सवेर उनका उभरना निश्चित है।

कॉमरेड्स, हमारे देश में भी चाहे जो भी राजनैतिक संकट हो, असंतोष की चिंगारियाँ हमारे चारों ओर उठ रही हैं, यहाँ वहाँ स्वत:स्फूर्त आन्दोलन भी समय-समय पर फूट पड़ रहे हैं। समय की मांग है नेतृत्व जो इन संघर्षों को इनके तार्किक अंजाम पर पहुँचा सके। कौन नेतृत्व दे सकता है? केवल वामपंथी पार्टियाँ संयुक्त रूप से नेतृत्व दे सकती हैं। संघर्षशील विचारधारा और उच्च नैतिकता द्वारा ही आन्दोलनों को चलाना होगा।

हमारी पार्टी हमेशा संयुक्त वामपंथी आन्दोलन की सदा पक्षधर रही है और आज भी है। अतीत में आप और हम संयुक्त वामपंथी आन्दोलन में एक साथ थे। लेकिन 1974 से हम आपकी पार्टी के साथ एकता में नहीं रहे। जब आपकी पार्टी पश्चिम बंगाल और केरल में सत्तासीन थी तब आपके साथ हमारे मतभेद थे और हमने लोगों के ज्वलंत मुद्दों पर आन्दोलन भी संगठित किए थे। हमारे सम्बंध कटु हो गए तथा कई दुखद घटनाएं भी घटीं। फिर भी, उस समय भी हमने अखिल भारतीय स्तर पर और अन्य राज्यों में आपके साथ एकता कायम करने का प्रयास किया लेकिन यह सफल नहीं हुआ। अब वह दौर गुजर चुका है। मैं कॉमरेड प्रकाश करात की सराहना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संयुक्त आन्दोलन की अपील लेकर हमसे मिलने के लिए कोलकाता जाने की तकलीफ उठाई। हमने मुद्दा आधारित संयुक्त आन्दोलन के लिए हार्दिक प्रत्युत्तर दिया। हम चुनावी लाभ के लिए एकता नहीं चाहते हैं बल्कि सिर्फ जुझारू वर्ग और जन संघर्षों के लिए एकता चाहते हैं। हाँ, सैद्धांतिक मतभेद होंगे और तदनुसार सैद्धान्तिक संघर्ष भी होगा लेकिन वह एकता और आन्दोलन को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए होगा। उन्नत विचारधारा और संस्कृति के आधार पर मेहनतकश लोगों के जुझारू वर्गसंघर्षों और जनआन्दोलनों को संगठित करना आज समय की मांग है।

मैं अपनी बात खत्म करने से पहले लेनिन की इस शिक्षा की याद दिलाना चाहता हूँ कि एक सर्वहारा पार्टी की असल शक्ति इसमें निहित नहीं है कि संसद में उसके कितने सदस्य हैं बल्कि वह वर्ग संघर्ष और जनसंघर्षों की तपिश में ही निहित है।

आप सभी को लाल सलाम।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद जिन्दाबाद

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद जिन्दाबाद

डॉ. शालिग्राम यादव स्मृति सभा

स्मृति सभा को सम्बोधित करते हुए सुमित राय

जमशेदपुर : ऑल इण्डिया शिक्षा बचाओ कमेटी, झारखण्ड राज्य कमेटी की ओर से कमेटी के प्रथम अध्यक्ष और झारखण्ड काउन्सिल के पूर्व चेयरमेन डॉ. शालिग्राम यादव की याद में 21 अप्रैल को यहां स्मृति सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता ऑल इण्डिया शिक्षा बचाओ कमेटी के अध्यक्ष प्रो. मितेश्वर ने की। सभा को कोल्हन विश्वविद्यालय के प्रो. वी.सी. डॉ. शुक्ला मोहन्ती, को-आपरेटिव कॉलेज के प्रिन्सिपल एसएस रजी, प्रभात खबर के सम्पादक रणजीत सिंह और शिक्षा बचाओ कमेटी, झारखण्ड चैप्टर के सचिव सुमित राय ने भी सम्बोधित किया।

किसानों को मुआवजा देने की मांग

अमरोहा, यू.पी.: बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से बर्बाद हुई प्रदेश के किसानों की फसल के नुकसान का मुआवजा दिलवाने व उनके कर्जे माफ करवाने की मांग को लेकर 18 अप्रैल को एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) की अमरोहा यूनिट के कार्यकर्ताओं ने जिला इंचार्ज कॉमरेड शील कुमार के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा।

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Printing : 5 May, 2015
सर्वहारा दृष्टिकोण
7 मई, 2015

कश्मीर में हत्याओं की एस.यू.सी.आई. (सी) ने की निन्दा

21 अप्रैल 2015 को एस.यू.सी.आई.(सी) महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया:

''सोशलिस्ट यूनिटी सैण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की केन्द्रीय कमेटी ने हाल ही में सैन्य अभियान के दौरान त्राल में दो युवकों के मारे जाने और 18 अप्रैल 2015 को बदगाम जिले के नरबल में प्रतिवाद प्रदर्शन के दौरान 16 साल के एक अन्य युवक हत्या की कड़े शब्दों में निन्दा करती है। ये घटनाएं सेना और अर्धसैनिक बलों को दी गई बेलगाम शक्ति को साफ तौर से दर्शाती हैं कि वे घाटी में अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ तक सुहेल नाम के 16 वर्षीय युवक की मौत का सवाल है मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पहले उसे सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिया गया और गोली मारने से पहले सवाल पूछे गए। ये घटनाएं पुन: आर्म्ड फोर्सिस स्पेशल पॉवर्स एक्ट (अफ्सपा) 1990, द कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 और अंतत: जे एण्ड के डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट जैसे कठोर जनविरोधी कानूनों को रद्द करने की जरूरत पर जोर देती है।

केन्द्रीय कमेटी कश्मीर सहित देश के लोगों से इन जन-विरोधी कानूनों के खिलाफ सशक्त और संयुक्त जनवादी-धर्मनिर्पेक्ष जन आन्दोलन निर्माण करने और इन कानूनों को वापस लेने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को मजबूर कर देने की अपील करती है। केन्द्रीय कमेटी का मानना है कि ऐसा एक आन्दोलन भारत के लोगों के साथ कश्मीर के लोगों के असल एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।''

सार्वजनिक स्थान पर कोई राजनैतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जमानत राशि जमा कराने की अनिवार्यता के बीजेपी सरकार के फैसले की एसयूसीआई(सी) ने की निन्दा

23 अप्रैल को एसयूसीआई(सी) महासचिव प्रभाष घोष ने निम्नलिखित बयान जारी किया:

''बीजेपी-नीत केन्द्रीय सरकार के तानाशाही फैसले की हम घोर निन्दा करते हैं कि किसी सामाजिक, राजनैतिक या पारिवारिक कार्यक्रम के लिए कोई सार्वजनिक स्थान बुक कराने के लिए आयोजकों को 10000 रुपए से लेकर 1 लाख तक की जमानत राशि जमा करानी होगी जिसे कार्यक्रम के बाद छ: घण्टे के अन्दर कार्यक्रम स्थल को साफ करने में चूक मान लिए जाने पर जब्त कर लिया जाएगा। स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के छद्मावरण में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम) के तहत जारी इस चालाकीपूर्ण फैसले का उद्देश्य जीवन की ज्वलंत मांगों को उठाने या किसी जनविरोधी कदम या सरकार के या निहित स्वार्थ के हलकों के क्रियाकलाप के खिलाफ न्यायसंगत प्रतिवाद की आवाज़ को उठाने के लिए मौजूदा जनवादी तौर तरीकों का पालन करते हुए मीटिंगें, रैलियाँ या प्रदर्शनों पर रोक लगाना है। इसलिए इस फैसले से ही प्रशासनिक फासीवाद की बू आती है जिसे मोदी-नीत बीजेपी सरकार धीरे-धीरे स्थापित करने पर आमादा है। यह शासक पूँजीपति वर्ग के घृणित वर्ग स्वार्थ की नग्न ताबेदारी करते हुए तमाम जनवादी मूल्यबोधों और सिद्धांतों को पैरों तले रौंद रही है और लोगों को उनके जो कुछ भी संघर्षों से अर्जित अधिकार हैं उन सभी से लोगों को महरूम कर रही है।

इसीलिए जनवादपसंद सही सोच रखने वाले लोगों को यह समझना निहायत जरूरी है कि यदि अनिष्टकर कदम बिना चुनौती रहे तो फासीवाद अपना शिकंजा कस देगा। इसलिए उन्हें पूरी पूरी तत्परता के साथ अपने को लामबंद करने की और सरकार के इस घोर दमनकारी फैसले के खिलाफ उठ खड़े होने की जरूरत है।

ईपीएफ की रकम को शेयर बाजार में लगाने का विरोध

ईपीएफ फण्ड का 5% धन शेयर बाजार में लगाने, जो 6.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर बैठता है, के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के फैसले का ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेण्टर (एआईयूटीयूसी) के महासचिव और सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, इम्पलाइज़ प्रोविडेण्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन के सदस्य कॉ. शंकर साहा ने 25 अप्रैल को जारी बयान में कड़ा विरोध किया। यह जमा धनराशि 14 करोड़ इपीएफ सदस्यों की है न कि 6 करोड़ सदस्यों की जैसा कि अखबारों में खबर छपी है।

उन्होंने कहा कि यह मजदूर-कर्मचारियों की कष्ट कमाई की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यह इसके शेयर बाजार में निवेशीकरण की बाढ़ ला देगा। यह मजदूरों का रिटायरमेण्ट के समय मिलने वाला रिटायरमेण्ट बेनिफिट माना जाता है। ट्रस्टीज़, इम्पलाइज़ प्रोविडेण्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन के केन्द्रीय बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने वाले केन्द्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं के संयुक्त विरोध के बावजूद वित्त मंत्रालय के कहने पर ऐसा किया जा रहा है। मजदूरों के रुपये को प्राइवेट बीमे और सट्टा बाजार में लगाना यूरोप और अमेरिका में पहले ही विनाशकारी साबित हो चुका है जहाँ मजदूर रिटायरमेण्ट के बाद कंगाल हो गए क्योंकि वे पूरा का पूरा पैसा प्राइवेट इक्विटी के साथ गवाँ बैठे हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्योगों में धननिवेश करना भी इसकी कोई गारण्टी नहीं करता है। एक सार्वजनिक उद्योग में 300 करोड़ के इपीएफओ के निवेशित धन की वसूली नहीं हो सकी क्योंकि उस कम्पनी को घाटा हो गया।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा दर्ज कराए विरोध के बावजूद नरेन्द्र मोदी ने कॉरपोरेट घरानों और एकाधिकारी पूँजीपतियों के प्रति अपनी शत प्रतिशत स्वामीभक्ति स्थापित करने के लिए यह 'दिलेरी' (!) दिखाई है।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस फैसले के खिलाफ दूसरों के साथ अखिल भारतीय हड़ताल की कार्रवाई करने की तारीख तय करने के लिए 26 मई 2015 को एक कन्वेन्शन बुलाई है। हम मजदूरों के हित में उनकी सुरक्षा के लिए इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हैं। हम इस हमले को नाकाम करने के लिए मजदूर बिरादरी से पुरजोर अपील करते हैं।

मोगा (पंजाब) में लड़की को बस से बाहर धकेल कर मौत के घाट उतारने का ए.आई.एम.एस.एस. द्वारा प्रतिवाद

30 अप्रैल को पंजाब के मोगा में बस सें सफर कर रही एक लड़की की दर्दनाक मौत की घटना का ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की दिल्ली राज्य कमेटी सचिव रितु कौशिक ने कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा:

अखबारों में आई खबर के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के परिवार की बस में सफर कर रही एक 14 वर्षीय लड़की के साथ बस के कंडक्टर व उसके साथियों ने छेड़छाड़ की। लड़की की माँ और लड़की द्वारा विरोध किये जाने पर उन्होंने माँ-बेटी को चलती बस से बाहर फेंक दिया। इससे लड़की की मौत हो गई और उसकी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है।

संगठन की दिल्ली राज्य कमेटी ने पंजाब सरकार से इस घटना की निष्पक्ष जाँच कराने, घटना की पूरी जिम्मेदारी प्रकाश सिंह बादल ले, दोषियों को उदाहरणमूलक सजा देने और लड़की के परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा देने तथा लड़की की माँ के इलाज पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किये जाने की मांग की।

शिक्षण शिविर आयोजित

मुम्बई में शिक्षण शिविर का संचालन करते हुए कॉमरेड छाया मुखर्जी

मुम्बई : कॉमरेड शिवदास घोष की कृति 'साम्प्रदायिक समस्या' नामक पुस्तक पर 26 अप्रैल को समता विद्या मन्दिर (स्कूल) मोहली गाँव, पाइप लाइन, साकी नाका, घाटकोपर-अंधेरी रोड, मुम्बई में एक दिन की क्लास लगाई गई। इसका संचालन एसयूसीआई(सी) की केन्द्रीय कमेटी सदस्या कॉमरेड छाया मुखर्जी ने किया। मुम्बई सब-अर्बन इलाके के अलावा नागपुर क्षेत्र के भी पार्टी समर्थकों, व कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर डीवाईओ की संगठक कॉ. प्रतिभा नायक भी उपस्थित रहीं।

पेट्रोल – डीजल के दाम बढ़ाने का कड़ा विरोध

रिवाड़ी, 1 मई : बढ़े पैट्रोल एवं डीजल के दामों के विरोध में एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के तत्त्वावधान में विक्षोभ प्रदर्शन किया एवं सरकार का पुतला फूँका। पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड राजेन्द्र सिँह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कॉ. सिंह ने कहा कि यह बढ़ोतरी जनविरोधी है, इससे तमाम आवश्यक चीजों के दाम बढ़ेंगे जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। भाजपा की सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुनाफे के लिए काम कर रही है। एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) ने मांग की है कि डीजल-पैट्रोल को सरकार अपने नियन्त्रण में ले। मेक इन इण्डिया पूँजीपतियों के हित में है, कांग्रेस ने उदारीकरण, निजीकरण की जिन नीतियों को लागू किया था, मोदी की सरकार उन्हीं को मेक इन इण्डिया के नाम से आगे बढ़ा रही है। प्रदर्शनकारियों को कृषक खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव रामकुमार, बलराम, राजबीर ने भी सम्बोधित किया।

फीस वृद्धि के खिलाफ हजारीबाग बंद

हजारीबाग : 27 अप्रैल को निजी स्कूलों की मनमानी और राज्य सरकार की उदासीनता के खिलाफ एक दिवसीय बंद सफल हुआ। विदित हो कि अभिभावक संघ एवं विभिन्न जनसंगठनों के द्वारा एक महीने से ज्यादा से आन्दोलन चलाया जा रहा था। आन्दोलन के क्रम में मशाल जुलूस, धरना और उसके बाद हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हजारों हस्ताक्षर के साथ-साथ जनसंपर्क अभियान चलाया गया।

बन्द के दौरान ही उपायुक्त ने वार्ता हेतु निमंत्रण दिया। 13 सूत्री मांगों में से 6 पर सार्थक चर्चा के बाद वार्ता समाप्त हुई। इस आन्दोलन में एआईडीएसओ एवं एआईएमएसएस ने अग्रणी भूमिका निभायी।

"Print-line
Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631